

मूल अधिकार की विशेषताएँ :-

(ii) मूल अधिकारों को सभी सरकारें मान्यता देने तथा सुयोजित करने का बाध्य है। यदि कोई सरकार मूल अधिकारों के अनुरूप काम नहीं करती तो न्यायपालिका उसका लागू करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकती है।

(iii) मूल अधिकारों की संरक्षित न्यायपालिका → यदि कोई व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार मूल अधिकारों का हनन करती है, तो व्यक्ति को सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। इसमें स्पष्ट है कि न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षित है।

(iv) सरकार की निरंकुशता पर अंकुश — मूल अधिकारों का सभी सरकारों पर एक अंकुश रहता है यानी कि कोई भी सरकार मूल अधिकारों पर अंकुश नहीं लगा सकती। वह मूल अधिकारों के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य है।

(v) कुछ अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। —
कुछ अधिकार भारत में रहने वाले

सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वे भारत के नागरिक हों अथवा नहीं, जैसे - जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ।

(vi) राष्ट्र तथा समाज हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध - संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिये गये हैं, व्यक्ति के अधिकारों से राष्ट्र तथा समाज का हित उच्च होगा है इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा तथा समाज के हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ।

(vii) मूल अधिकार भारत की परिस्थितियों के अनुरूप - मूल अधिकारों को भारत की परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर जीवनोपयोगी बनाया गया है अर्थात् व्यक्ति के जीवन में इनका बड़ा महत्व है ।

(viii) मूल अधिकारों को भारत के संविधान में स्थान - मूल अधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मूल अधिकारों को सर्वोच्च मूल - विधि में स्थान दिया गया है, अर्थात् मूल अधिकारों का विपक्ष

भारत के संविधान में दिया हुआ है।

* उक्त महत्वपूर्ण पन्तव्य :-

* मौखिक अधिकार वह है, जो राज्य के लिखित संविधान द्वारा सुरक्षित व कार्यान्वित होता है। इसे निर्धारित संशोधन विधि द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है, इसे किसी निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से खत्म या निलंबित नहीं किया जा सकता तथा राज्य का कोई अंग इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
दुर्गाहास शर्मा (D.D BASU)

* अधिकारों के बिना कोई खतरा नहीं हो सकती तथा हर राज्य की पहचान उसके द्वारा सुरक्षित अधिकारों से होती है।

Dr. Khushboo

Del — Political Science